

यशस्वी का एक
और शतक,
भारत मजबूत
>> 12

दैनिक जागरण

रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा भारत

टैरिफ वार के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भारत का करारा जवाब

नई दिल्ली, २२ अगस्त : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुर्मानी की धमकियों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि ये दीर्घकालिक तेल अनुबंध हैं। रातों-रात खरीदारी बंद करना इतना आसान नहीं है। ट्रंप ने पिछले महीने टूथ सोशल पर एक पोस्ट में संकेत दिया था कि रूसी हथियार और तेल खरीदने के लिए भारत को अतिरिक्त पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन, अमेरिका के साथ जारी टैरिफ वार के बीच रूस से तेल खरीद जारी रखने को भारत सरकार का करारा जवाब माना जा रहा है। भारत रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है।

भारत ने आधिकारिक रूप से इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया कि रूस से तेल आयात पर कोई रोक नहीं है। भारत की ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हितों और बाजार की ताकतों पर आधारित है। हमारे पास भारतीय तेल कंपनियों द्वारा रूसी आयात रोकने की कोई रिपोर्ट नहीं है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया था कि भारतीय रिफाइनरियों (इंडियन आयल कार्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन और मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड) ने पिछले सप्ताह

स्थिति स्पष्ट

भारतीय तेल रिफाइनरियों ने नहीं रोका है रूस से तेल आयात, मांग के आधार पर हो रही है खरीद

भारत की प्रतिक्रिया से पहले ट्रंप ने छोड़ा था शिगूफा-सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा



डोनाल्ड ट्रंप।

फाइल

रूस के साथ भारत की है स्थिर साझेदारी

विदेश मंत्रालय के प्रवक्त णधीर जायसवाल ने शुक्रवार को नियमित ब्रीफिंग के दौरान संवाददाताओं से कहा था कि ऊर्जा जरूरतों के संदर्भ में हम बाजार में उपलब्ध विकल्पों और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों पर नजर रखते हैं। रूस के साथ भारत की स्थिर साझेदारी है, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। विभिन्न देशों के साथ नई दिल्ली के संबंध अपनी-अपनी योग्यता के आधार पर हैं। इन्हें किसी तीसरे देश के नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए।

रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन, आइएएसएस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि चारों रिफाइनरियां नियमित रूप से मांग के आधार पर रूसी तेल खरीदती हैं और वैकल्पिक रूप से पश्चिम एशिया और अफ्रीकी बाजारों का रुख कर रही हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वैश्विक बाजार की पैशकशों के आधार पर तेल खरीदता है। न्यूयार्क टाइम्स ने शनिवार को दो बरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के हवाले से

कहा कि भारत सरकार की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

एक अधिकारी ने कहा कि सरकार ने रूस से आयात कम करने के लिए तेल कंपनियों को कोई निर्देश नहीं दिया है। समाचार एजेंसी रयटर ने इसी सप्ताह बताया था कि जुलाई में छूट कम होने के बाद भारत की सरकारी तेल रिफाइनरियों ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है। प्रेट्ट के अनुसार, भारत की प्रतिक्रिया से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने शिगूफा छोड़

भारत रूस से तेल नहीं खरीदे तो वैश्विक स्तर कीमतें हो सकती हैं 200 डालर प्रति बैरल

नई दिल्ली, एएफआई: भारत अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 200 डालर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं, जिससे दुनियाभर के उपभोक्ताओं को भारी नुकसान होगा। अधिकारियों का कहना है कि रूसी तेल पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। न तो अमेरिका और न ही यूरोपीय संघ ने अब तक कोई प्रतिबंध लगाया है। वैश्विक बाजारों से रूसी तेल के बाहर होने की पिछली आशकाओं के चलते कूछ की कीमतें मार्च 2022 में 137 डालर प्रति बैरल के उच्च स्तर तक पहुंच गई थीं। भारत अपनी जरूरतों के लिए 85% आयात पर निर्भर है।

था कि उन्होंने सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने इसे एक अच्छा कदम बताया, लेकिन साथ ही कहा कि उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मुझे पता चला है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मैंने यही सुना है। मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत, लेकिन यह एक अच्छा कदम है। देखते हैं क्या होता है।

गुलाम जम्मू-कश्मीर में स्थानीय लोगों ने लश्कर के आतंकियों को पीटकर भगाया

सीन नज़ा ● जागरण

श्रीनगर : गुलाम जम्मू-कश्मीर में अब आतंकवाद और स्थानीय युवाओं को जिहाद की आग में धकेलने वालों के खिलाफ खुली बगावत होने लगी है। यही कारण है कि जब श्रीनगर के दार्चीगाम में आपरेशन महादेव में मारे गए तीन आतंकियों में से एक की गुलाम जम्मू-कश्मीर में हुई गायबाना नमाज-ए-जनाजा में लश्कर-ए-तैय्यबा के कमांडर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें पीटकर भाग दिया। लोगों ने साफ कहा कि हम आतंकियों द्वाा स्थानीय युवाओं को उनके जिहादी एजेंडे के लिए स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। इस घटना से एक बार फिर साफ हो गया कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को लश्कर ने ही तैयार किया था।

श्रीनगर के साथ सटे दार्चीगाम में 28 जुलाई को सुरक्षाबल ने आपरेशन महादेव चलाकर तीन पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया था। ये तीनों 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की हत्या और बीते वर्ष सोमनगर के गगनगौर में सात लोगों की हत्या के लिए भी जिम्मेदार थे। आपरेशन में पहलगाम हमले का मुख्य गुनहगार अपने दो अन्य साथियों संग मारा गया था। उसके दो अन्य साथियों में एक गुलाम जम्मू-कश्मीर का रहने वाला था। वह रावलाकोट के साथ सटे कोईयां खेई गला क्षेत्र का निवासी था। बताया जाता है उसे लश्कर के मजहबी गतिविधियों पर केंद्रित संगठन जमातुल दवा के रिक्रुटर अनीस रिजवान के जिहादी गतिविधियों के लिए तैयार किया था। अनीस रिजवान के बारे में कहा जाता है कि वह भी कश्मीर में सक्रिय रह चुका है।

आपरेशन महादेव में मारे गए तीन आतंकियों में से एक के गायबाना नमाज-ए-जनाजा में आए थे आतंकी

लोग बोले- स्थानीय युवाओं को जिहाद के नाम पर गुमराह नहीं होने देंगे, पुलिस से की शिकायत

बच्चों को जिहाद के नाम पर मरने नहीं भेजेंगे

बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन और एसडीएम हाइवे रोल के समक्ष लिखित में अनीस रिजवान और उसके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि जब क्षेत्र में हथियारबंद लोगों के किसी जगह जमा होने पर पाबंदी है तो ये लोग कैसे घूम रहे हैं। कोईयां और उसके आसपास के गांवों के लोगों ने एक जिरगा (बैठक) भी बुलाने का एलान किया है। उसमें जिहादी संगठन के लोगों की आवाजही और स्थानीय युवाओं की कश्मीर के नाम पर जिहादी संगठनों में भर्ती पर पूरी तरह पाबंदी लगाए जाने पर चर्चा होगी। लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे जिहाद के नाम पर सुली चढ़ाने के लिए नहीं हैं।

लोगों ने करथा था एलान-कोई जिहादी कमांडर न आए : आतंकी की मौत की खबर मिलने के बाद से उसके गांव के लोगों में लश्कर कमांडरों के प्रति शेष था। उसकी मौत पर गत शुक्रवार को कोईयां में स्थानीय ग्रामीणों ने गावबाना नमाज-ए-जनाजा का आयोजन किया था। बता दें कि मृतक का शव न होने पर पड़े जाने वाली नमाज को गायबाना नमाज-ए-जनाजा कहा जाता है। उसके परिजनों ने की मरिजद से एलान कराया था कि नमाज-ए-जनाजा में कोई भी जिहादी कमांडर या उनका कोई साथी शामिल नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके लश्कर कमांडर अनीस रिजवान अपने साथियों संग पहुंच गया था।

मोदी और भागवत को फंसाने के लिए मुझे दी गई यातनाएं: प्रज्ञा

मुंबई, प्रेट्ट : मालेगांव विस्फोट मामले में बरी की गई पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शनिवार को आरोप लगाया कि जांच अधिकारियों ने उन्हें प्रताड़ित किया और उनसे गुजरना के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत सहित कई लोगों के नाम लेने को कहा। यह पहली बार है, जब साध्वी प्रज्ञा ने यह सनसनीखेज दावा किया है। विशेष एनआइए अदालत ने इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सहित सभी सात आरोपितों को बरी कर दिया है। हालांकि, विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने अपने फैसले में प्रज्ञा ठाकुर को प्रताड़ित करने और दुर्व्यवहार के दावों को खारिज कर दिया था। पूर्व भाजपा सांसद शनिवार को अपनी जमानत की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए यहां सत्र न्यायालय में पेश हुईं। बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि पूछताछ के दौरान उन्हें प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा- अधिकारियों ने



साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर।

फाइल

मुझे मोदीजी का नाम लेने के लिए कहा था, क्योंकि उस समय मैं सूरत में रह रही थी। भागवत (आरएसएस प्रमुख) जैसे कई नाम हैं। लेकिन, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी। साध्वी प्रज्ञा ने कहा, उनका उद्देश्य मुझे प्रताड़ित करना था। उन्होंने कहा कि अगर मैंने नाम नहीं लिए तो वे मुझे प्रताड़ित करेंगे। इन नामों में योगी आदित्यनाथ, सुदर्शनजी, इंद्रेजजी, राम माधव और कई अन्य नाम

एक गवाह का दावा-योगी आदित्यनाथ को भी फंसाने की थी साजिश

मालेगांव विस्फोट मामले में एक गवाह ने विशेष अदालत में आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र एटीएस के अधिकारियों ने उसे प्रताड़ित किया और मामले में योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए मजबूर किया। विशेष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एटीएस ने अक्टूबर 2008 में अभियोजन पक्ष के गवाह मिलिंद जोशीराव से अभिनव भारत संगठन की कार्यप्रणाली के बारे में पूछताछ की थी। उनसे रायमढ़ फिले में हुई

शामिल हैं, जिन्हें मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूं। मुझे असफल में भी अवैध रूप से हिरासत में रखा गया, जहां मैं बेहोशा हो गई और मेरे फेफड़े खराब हो गए। उन्होंने कहा, मैं अपनी कहानी लिख रही हूं, जिसमें मैं यह सब बताऊंगी। सच्चाई सामने आएगी। यह धर्म की जीत है, समातन की जीत है और हिंदुत्व की जीत है। यह एक समातनी राष्ट्र है और इसकी हमेशा जीत होती है। उन्होंने मुझे प्रताड़ित करने और देश

सभी भक्तों को इसमें शामिल करने की बहुत कोशिश की... हम कोशिश करेंगे कि उन्हें सजा मिले। उन्होंने महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) के तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के एक दृष्ट व्यक्ति बताया। कहा कि परमबीर सिंह, हेमंत करकरे और सुखविंदर सिंह ने मुझे प्रताड़ित किया और मुझसे झूठ बोलने को कहा। लेकिन, मैंने झुंकार कर दिया।

काशी में पीएम बोले- वैश्विक अस्थिरता के माहौल में आर्थिक हितों के प्रति हमें सजग रहना होगा

प्रधानमंत्री ने महादेव के वरुणों में समर्पित की आपरेशन सिंदूर की सफलता

विपक्ष पर साधा निशाना- वरुणों के सिंदूर के बदले को तमाशा कहना निर्लज्जता



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए। एएनआई

यहीं से प्रणाम कर रहा हूं।' मोदी ने आपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में बयान के लिए कांग्रेस और सपा को भी निशाने पर रखा। कहा कि दुर्भाग्य से आपरेशन सिंदूर की सफलता से देश के ही कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस ने जवानों के पराक्रम का लगातार अपमान किया और आपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। क्या सिंदूर कभी तमाशा हो सकता है? हमारी सेना के पराक्रम, महादेव के चरणों में समर्पित करता हूं। काशी विश्वनाथ और मार्कंडेय महादेव के दर्शन की इच्छा थी, लेकिन मेरे वहां जाने से भक्तों को दिक्कत होती, इसके लिए

नेता संसद में कह रहे थे कि पहलगाम के आतंकी को क्यों मारा? बोले- नया भारत भोलेनाथ को पूजता है तो समय आने पर लुमनों के सामने कालभैरव भी बनता है। जब आतंक और अन्याय होता है तब महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। आज भारत पर जो बार करेगा, वह पाताल में भी नहीं बचेगा। आपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों खासकर ब्रह्मोस मिसाइलों ने ताकत साबित की। इसका निर्माण अब लखनऊ में किया जाएगा। पीएम की अपील, जनघन खातों की केवाईसी की आवश्यकता करें पूरी पेज>>3

रविवार विशेष

स्वच्छता का संस्कार

सफलता का मुकाम

● पेज-7

संपादकीय

एक चिट्ठा हुआ शासनाध्यक्ष : भारत स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहा है और उसे यह तय करने का अधिकार है कि किसी देश से किन वस्तुओं को खरीदे और किन्हे नहीं। संजय गुप्त का आलेख।

संपत्ति, आपत्ति और विपत्ति का त्रिकोण : महाभारत काल से जारी सभी लड़ाइयां संपत्ति पर आपत्ति का ही प्रमाण हैं। जिन्हें विपत्ति बनने में देर नहीं लगती। सूर्यकुमार पांडेय का व्यंग्य। ● पेज-8

विमर्श

लंकेश्वर फिल्मों-कलकारों को सम्मान : वर्ष 2023 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। शाह रुख खान को फिल्म 'जवान' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा चौकाने वाला लग रहा है। अनंत विजय का आलेख। ● पेज-9

दुष्कर्म मामले में प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा

बंगलुरु : विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व सांसद और निर्लक्षित जहाजस नेता प्रज्वल रेवन्ना को घरेलू सहायिका से दुष्कर्म के मामले में शेष जीवन के लिए कैद की सजा सुनाई। विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौडा के पौत्र पर कुल 11.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि इसमें से 11.25 लाख पीडित महिला को दिया जाए। (पेज-6)

मालेगांव धमाका मामला

अदालत के फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने सुनाई दर्दनाक वरतां, विशेष अदालत ने प्रज्ञा सहित सभी सात आरोपितों को कर दिया है बरी

'रात की पार्टियों में न जाएं, हो सकता है सामूहिक दुष्कर्म'

रज्य ब्यूरो, जागरण ● अहमदाबाद

अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस के सुरक्षा अभियान के पोस्टरों ने विवाद खड़ा कर दिया है। इनमें से कुछ पोस्टरों में अजीब सलाह देते हुए महिलाओं से घर पर रहने का आग्रह किया गया है ताकि वे दुष्कर्म से बच सकें। पोस्टरों में चेतावनी भरे संदेश लिखे हैं। युवतियों को सलाह दी गई है कि रात की पार्टी में न जाएं, वहां सामूहिक दुष्कर्म हो सकता है। अंधेरे व सुनसान जगह पर युवक महिला मित्र को लेकर नहीं जाएं, वहां भी दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म हो सकता है। विरोध के बाद पोस्टर हटा दिए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। यातायात पुलिस ने इन पोस्टरों को लगाने की जिम्मेदारी एक संस्था पर डाल कर पल्ला झाड़ लिया लेकिन समाजिक कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा के नाम पर बोर्ड

अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस के सुरक्षा अभियान के पोस्टर में दी गई सलाह

घर में रहें दुष्कर्म से बचें, आपत्ति के बाद पल्ला झाड़ा, पोस्टर हटाए

लगा कर इतिश्री मान लेने वाली पुलिस की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। अहमदाबाद के सबसे पश्चा व मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के विधानसभा क्षेत्र घाटलोडिया, सोला, साईस सिटी, जजेज बंगलो, डमरु सर्कल आदि स्थलों पर महिलाओं व युवतियों की सुरक्षा के नाम पर जो चेतावनी भरे बोर्ड लगाए गए, उन्हें देखकर लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। युवक व युवती को गुजरती नाटक के चर्चित पात्र रंगला और रंगली कहकर संबोधित किया गया है।

पुलिस ने कहा, बरौर अनुमति पंजीओने तैयार किए पोस्टर पेज>>7

फसल बाजारों तक पहुंचाने का खर्च वहन करेगी सरकार

शिवराज बोले, प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना शुरू करेगी केंद्र सरकार

कहा, खाद-बीज की कालाबाजारी करने वालों को जेल भेजें

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना



बिहार में किसान उत्सव दिवस के रूप में शनिवार को बापू सभागार में राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के साथ राज्य के 73.88 लाख किसानों के खाते में शनिवार को 1515 करोड़ रुपये भेजे गए। इस मौके पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि सब्जी या अन्य फसल अब खराब नहीं होगी। उसे ट्रक में भरकर दिल्ली या दूसरे शहरों के बाजारों तक पहुंचाने का खर्च सरकार देगी। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। शीघ्र ही केंद्र सरकार प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना को शुरुआत करेगी। इससे किसानों का मुनाफा बढ़ेगा।

शिवराज ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय एक रुपये में 15 पैसे किसानों तक पहुंचते थे, आज एक-एक रुपया

जस्टिस मनमोहन बोले, दिव्यांगों के अधिकारों पर जागरूकता की जरूरत

नई दिल्ली, प्रे़ट : सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मनमोहन ने दिव्यांगों के अधिकारों के बारे में संबैदशाीलता और जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने शनिवार को कहा कि न्यायालयों ने दिव्यांगों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर फैसले सुनाए हैं और सुनाएंगे, लेकिन सरकार के अन्य अंगों को भी इस विषय पर आगे आना होगा। जस्टिस मनमोहन यहां 'दिव्यांगजनों के अधिकार' विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में बोल रहे थे। यह सम्मेलन जस्टिस सुनैव बंधारे फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था।

उनसे जब फैसलों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि इस विषय पर कानून और अधिकारों के बारे में जितनी अधिक जागरूकता होगी, समाज उतना ही अधिक समझेगा, अदालतें उतना ही अधिक समझेंगी और इससे अनुपालन सुनिश्चित होगा।'

उन्होंने फैसलों के अनुकूलन के लिए अदालत द्वारा निरंतर निगरानी के मुद्दे पर भी बात की।

निजी स्कूलों की फीस तय कर सकती है राज्य सरकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने का अधिकार रखती है। कोर्ट ने फीस विनियमन अधिनियम 2020 को संवैधानिक मानते हुए निजी स्कूलों की यचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की बेंच ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में मुनाफाखोरी और शोषण पर नियंत्रण के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना राज्य सरकार का संवैधानिक अधिकार है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि निजी स्कूलों की स्वायत्तता बनी रहेगी, लेकिन फीस के नाम पर मनमानी वसूली पर सख्त नियंत्रण आवश्यक है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन और बिलासपुर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इस अधिनियम को असंवैधानिक बताते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि यह स्कूलों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करता है।

सेहतकारी भोजन

एफएसएसएआइ ने जारी की आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों की सूची, इसपहल से भारतीय शाश्वत संस्कृति और सेहत का होगा संगम

नई दिल्ली, एनएआइ : आयुर्वेद अब ग्रंथों तक नहीं रहेगा, बल्कि घर-घर में खाने की थाली तक पहुंचेगा। आयुर्वेद आहार को एफएसएसएआइ से मान्यता मिल गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने आयुष मंत्रालय के परामर्श से 'आयुर्वेद आहार' श्रेणी के तहत आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों की सूची जारी की है। आयुर्वेद आहार वे खाद्य पदार्थ होते हैं जो आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। इनमें सब्जियां और मसालों से लेकर, विशेष आयुर्वेदिक व्यंजनों और औषधीय गुणों वाले खाद्य पदार्थ हो सकते हैं। ये खाद्य उत्पाद प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर तैयार किए जाते हैं, जिनमें पोषण, संतुलन और परंपरा का सम्मिश्रण होता है ताकि समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले।

आयुष मंत्रालय ने कहा है कि नई सूची से प्रामाणिक आयुर्वेदिक ग्रंथों से प्राप्त व्यंजनों, अवयवों और प्रक्रियाओं पर आधारित खाद्य पदार्थों को मान्यता मिल गई है। 2022 में खाद्य सुरक्षा और मानक (आयुर्वेद आहार)

आयुर्वेद आहार वे खाद्य पदार्थ होते हैं, जो आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार किए जाते हैं तैयार



प्रतीकात्मक

विनियमों की शुरुआत के बाद भारत के पारंपरिक खाद्य ज्ञान को घर-घर तक पहुंचाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। इससे प्रामाणिक आयुर्वेदिक ग्रंथों से प्राप्त व्यंजनों, अवयवों और प्रक्रियाओं पर आधारित खाद्य पदार्थों को मान्यता मिल गई है।

विनियमों या रेगुलेशन की अनुसूची बी

उत्तराखंड के वनों

की हकीकत बताएंगी

सेटेलाइट तकनीक

विजय जोशी, जागरण • देहवाड़न:

उत्तराखंड में वन प्रबंधन की नई इबारत लिखी जा रही है। अत्याधुनिक सेटेलाइट तकनीक से प्रदेश के वनों की हकीकत जानी जाएगी और वन, वनस्पति व सामुदायिक संरक्षण की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए वन विभाग ने सीमांत जनपद पिथौरागढ़ व चंपावत में वनों के संरक्षण, संवर्धन और सामुदायिक सहभागिता के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है। दोनों जनपदों की 10 वर्षीय पुनरीक्षित कार्य योजनाएं (2024-25 से 2033-34) तकनीकी नवाचार, जैवबिबिधता संरक्षण, सतत आजीविका, पर्यावरणीय अनुकूलन और सामाजिक सरोकारों को केंद्र में रखकर तैयार की गई हैं। केंद्रीय की ओर से भी उक्त कार्ययोजना को हरी झंडी मिल गई है। ये योजनाएं प्रदेश के वानिकी प्रबंधन को बितानी, समावेशी और सुदृढ़ दिशा प्रदान करने की ओर एक कदम होगा।

उक्त दोनों वन प्रभागों में पहली बार इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट आइआरएस-पी6 के लीनियर इमेजिंग सेलेफ स्कैनिंग सेंसर (एलआइएसएस-चार) सेंसर (5.8 एम रेजोल्यूशन) का प्रयोग किया गया है, जो पारंपरिक एलआइएसएस-तीन (23.5 एम) की तुलना में चार गुना अधिक स्पष्ट और सटीक है। इससे वन प्रकारों और वन मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने की।

हरियाणा में सात अगस्त के बाद आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं : आइएमए

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) के हरियाणा चैप्टर ने सात अगस्त से आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं करने का फैसला किया है। आइएमए को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों के पूर्व के पैसे का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। राज्य में करीब 650 निजी अस्पताल आयुष्मान तहत-आयुष्मान हरियाणा योजना के तहत कार्डधारकों का इलाज कर रहे हैं। इनका करीब 400 करोड़ रुपये बकाया चल रहा है, जिसके भुगतान के लिए पत्र व्यवहार किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।

आइएमए हरियाणा के अध्यक्ष डा. महावीर पी जैन, पूर्व प्रधान डा. अजय महाजन, महासचिव डा. धीरेन्द्र के सोनी और आइएमए के आयुष्मान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डा. सुरेश अरोड़ा ने आयुष्मान प्राधिकरण हरियाणा की कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखकर सात अगस्त

आइएमए ने सरकार को लिखा पत्र, लंबित 400 करोड़ का भुगतान मांगा

सरकार के साथ दो बार की बैठकों के बावजूद नहीं हुआ भुगतान



प्रतीकात्मक

से कार्डधारकों का इलाज नहीं करने की सूचना दे दी है। उन्होंने सरकार के साथ पिछली सभी बैठकों का जिक्र करते हुए भी तर्क भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही कहा है कि यदि आयुष्मान कार्डधारकों का इलाज नहीं होता तो इसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग के उन अधिकारियों की होगी, जो बैठकें करने के बावजूद उनमें होने वाले फैसले

दोगुना हुआ बीएलओ का मानदेय, ईआरओ और ईईआरओ को भी अब मिलेगा मानदेय

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण में लगे वीएलओ के वार्षिक मानदेय छह हजार से बढ़ाकर किया 12 हजार रुपये

ईआरओ को 30 तो ईईआरओ को 25 हजार मिलेंगे, विहार में एसआइआर में लगे वीएलओ को अतिरिक्त छह हजार



आयोग के मूताबिक मानदेय में की गई बढ़ोतरी पूरे देशभर में लागू होगी। इससे पहले बीएलओ के मानदेय में बढ़ोतरी वर्ष 2015 में की गई थी।

आयोग के मूताबिक शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है। ऐसे में इस काम लगे बीएलओ सहित दूसरे कर्मचारियों की मेहनत को देखते हुए उनके मानदेय में यह बढ़ोतरी की गई हो। इन्हें यह वार्षिक मानदेय इसलिए दिया जाता है, क्योंकि देशभर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम साल में एक बार होता है।

यह बात अलग है कि यदि किसी राज्य

बढ़ोतरी पर एक नजर

पदनाम	2015 में	अब संशोधित
बीएलओ	6 हजार	12 हजार
बीएलओ प्रोत्साहन राशि	एक हजार	दो हजार
बीएलओ पर्यवेक्षक	12 हजार	18 हजार
ईईआरओ	शून्य	25 हजार
ईआरओ	शून्य	30 हजार

में साल के मध्य में चुनाव होता है, तो वहां फिर से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य होता है। उसके लिए उन्हें फिर से यह मानदेय दिया जाता है।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने यह फैसला तब लिया है, जब बिहार में एसआइआर के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। साथ ही द्वापट मतदाता सूची भी आ चुकी है। इस सूची को तैयार करने के लिए बीएलओ की ओर से घर-घर जाकर जानकारी जुटाई गई थी। अब इस पर आपत्तियों के लिए एक महीने का समय मिलेगा, जो एक सितंबर तक की अवधि होगी।

इतिहास के पुनर्लेखन पर विचार करें लेखक : मनोज सिन्हा

राज्य ब्यूरो, जागरण • श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को लेखकों से इतिहास के पुनर्लेखन पर विचार करने का आह्वान किया, ताकि अतीत में विकृत किए गए तथ्यों को सही किया जा सके। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को यह अहसास दिलाना जाना चाहिए कि हमारी सभ्यता आर्थिक रूप से समृद्ध थी और साहित्य, विज्ञान और अध्यात्म का वैश्विक केंद्र थी थी। उपराज्यपाल ने श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित श्रेे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मप्र प्रधान के साथ चिनार पुस्तक महोत्सव-2025 का उद्घाटन किया।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यस, शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद (एनसीपीयूएल) और श्रीनगर जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित चिनार पुस्तक महोत्सव में देशभर से 200 से अधिक प्रकाशकों और पुस्तक स्टालों की भागीदारी है। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी और अन्य भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रदर्शित की जा रही हैं।

पीएम की अपील, जनधन खातों की केवाईसी की आवश्यकता करें पूरी

ग्रथम गृट से आगे

जनधन खातों से आए बदलाव का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी प्राथमिकता मिले। इसी उद्देश्य से 10 वर्ष पहले 55 करोड़ गरीबों के जनधन खाते खोले गए। बैंक नियम में 10 वर्षों बाद नए सिरे से केवाईसी की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक जुलाई से राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। सबसे अपील है कि वे जनधन खातों की केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करा लें। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना जैसी अनेक योजनाओं का भी लाभ उठाएँ।

20वीं क्रिस् जारी कर मोदी बोले-फक्के इस्ती का उद्घरण किसान सम्मान निधि : इस अवसर पर किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं क्रिस् के तहत 9.70 करोड़ किसानों के खाते में 20,500 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री ने आनलाइन ट्रान्सफर किए। बोले, 2019 में धन योजना शुरू हुई थी तो सपा, कांग्रेस ने कहा था कि

कह कर रहेंगे

माधव जोशी



‘शहर की गड़बड़ार सड़कों को पार कर सुरक्षित घर वापसी के लिए आपको बधाई!’

संभल के पहल वहाँ
संभल के पहल वहाँ

